RAJYA SABHA

i *Thursday, the* 17th *August,* 1978/ the 26th *Sravana,* 1900 (Saka)

The House met at eleven of the clock, Mr. Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Sick Industries

•661. SHRI SHYAM LAL YADAV: t SHRI T. ANJIAH: SHRI N. G. RANGA: t

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what is the number of sick in dustries which are closed on that ac count or for *some* other reasons dur ing 1977-78; and

(b) what steps Government pro poses to improve the functioning of other sick industries which have not been taken over by Government?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) and (b) A statement is laid on the Tahlo *nt* the TTntiop

Statement

The industry-wise information regarding the industrial units lying closed in the country and details pertaining to them are not centrally maintained in this Ministry. However, information which is centrally collected by the Ministry of Labour on factories registered under the Factories Act, 1948, which are lying closed for long or short duration is given in standard tabulated forms published in the Indian Labour Journal which is a monthly publication of the Labour Bureau, Government of India. Copies of the publication are available in Parliament House Library. According to the June, 1978 edition of the Indian Labour Journal, 19 factories registered under- the Factories Act, 1948 had to close during March, 1978 for reasons other than industrial disputes affecting 822 workers. The details are given in the annexure.

The Statement on Policy on Sick industries, which was announced" in Parliament on 15-5-1978, outlines the steps which the Government proposes to take in respect of sick units, whose management is not taken over by it.

Annexure

Information on closures of Factories registered under the Factories Act, 1948 for reasons other than Industrial Disputes

Sl. No.	State/Union Territory	February, 1978(P)		March, 1978 (P)	
		No. of cases	No. of workers affected	No. of cases	No. of workers affected
1	Andhra Pradesh	..	..	..	..
2	Assam	..	..	..	..
3	Bihar	..	..	1	80
4	Gujarat	4	200	6	251
5	Haryana	1	15	—	—
6	Himachal Pradesh	..	..	..	..

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Shyam Lal Yadav.

Sl. No.	State/Union Territory	February, 1978(P) No. of cases	February, 1978(P) No. of workers affected	March, 1978(P) No. of cases	March, 1978(P) No. of workers affected
7	Jammu & Kashmir	—	—	—	—
8	Karnataka	1	492	—	..
9	Kerala	—	—	—	—
10	Madhya Pradesh	—	—	—	..
11	Maharashtra	—	—	—	—
12	Manipur	—	—	—	—
13	Meghalaya	—	—	—	—
14	Nagaland	—	—	—	—
15	Orissa	—	—	2	110
16	Punjab	1	25	—	—
17	Rajasthan	..	..	..	—
18	Sikkim	..	—	..	..
19	Tamil Nadu	—	—	..	..
20	Tripura	—	—	—	—
21	Uttar Pradesh	—	—	—	—
22	West Bengal	—	—	10	381
	Union Territory				
1	Andaman & Nicobar Islands	1	30	—	..
2	Arunachal Pradesh	—	—	..	..
3	Chandigarh	—	—	—	—
4	Dadra and Nagar Haveli	—	—	..	..
5	Delhi	1	17	—	..
6	Goa, Daman and Diu	—	—	—	—
7	Lakshdweep	—	—	..	..
8	Mizoram	..	..	..	..
9	Pondicherry	—	—	—	—
	TOTAL	12	874	19	822

—Nil .. Not available (P) Provisional

NOTE— The figures are based on the return received in the Bureau up to the 18th May, 1978.

SOURCE.—Indian Labour Journal, June, 1978 edition, pages 866-867.

P.S.—Infsrmitn-i about closures of factories registered under the Factories Act, 1948 (due to reasons other than Industrial closures) during March, 1978 is based on the monthly news returns received from different States in the Labour Bureau.

श्री श्याम लाल यादव : मान्यवर, मंत्री जी ने जो बयान सदन के पटल पर रखा है उसको मैंने देखा । उससे हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचते । उन्होंने अपने उत्तर में न तो समस्या की गहराई पर कोई प्रकाश डाला है और न ही इसके लिए क्या उन्होंने कदम उठाने की बात सोची हैं, जैसा (ख) में है, उस तरफ़ कोई ध्यान दिलाया है । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह बतलायेंगे कि उन उद्योगों के रुग्ण या सिक होने के मूलभूत कारण क्या है ? क्या यह बात सही नहीं है कि इनमें जो रुग्ण हैं उनमें अधिकांश सितम्बर, 1977 की जो फिगर्स उपलब्ध है उनके अनुसार--इंजीनियरिंग की 72 यूनिट्स, टैक्सटाइल की, नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन को छोड़कर, 68 यूनिट्स जूट की 29, शुगर की 23, आयरन एण्ड स्टील की 19, कैमिकल्स की 15-- सब मिलाकर 270 यूनिट्स थीं जिसमें कि कुल 773.70 करोड़ रुपये बैंकों के लगे थे। ऐसी भयंकर स्थिति में क्या मंत्री जी इस प्रकार की बात कहकर कि इनकी संख्या लेबर डिपार्टमेंट इकट्ठी करता है, इससे सन्तोष धारण करेंगे और देश को करायेंगे ? क्या यह बात सही नहीं है कि ये जो इंडस्ट्रीज सिक हुई वह इसलिए हुई कि इनके उद्योगपति इन उद्योग धंधों से बराबर मुनाफ़ा चूसते रहे और उनमें कोई रुपया दुबारा लगाया नहीं। न उनकी मशीनरी में किसी प्रकार का सुधार किया, न हमारे देश में जो ऐडवांस्ड टैक्नालाजी उपलब्ध थी उसके मुताबिक मशीनों का सुधार किया । क्या मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो सिक नहीं हैं भविष्य में वह सिक न हों, उनको रोकने के लिए क्या ऐडवांस्ड टक्नालाजी लगायेंगे, ऐसा प्रयास उन्होंने किया है ? श्रीमन् इसके दो अंग है, एक तो जो यूनिट्स सिक हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की और दूसरे भविष्य में यूनिट्स सिक न हो जायें, उनके लिए क्या योजना बनाई है ? इसी तरह से कैपिटल इक्विपमेंट्स, जिनकी बुक वैल्यू 25 प्रतिशत से कम हो चुकी है, उनको रिप्लेस करेंगे जिससे कि हमारे देश के उद्योगों की जो कैपैसिटी है उसका पुनर्निर्माण हो सके ?

श्री जार्ज फ़र्नांडीस : सभापति महोदय, 15 मई, 1978 को हमने इस सदन में और लोक सभा में भी ये तमाम सिक इंडस्ट्रीज जो हैं, उनके बारे में सरकार की नीति का बहुत विस्तृत बयान दिया था । माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, इन सारे सवालों का जवाब हमारे लिए देना मुश्किल है कि जिस प्रकार की स्टेटिस्टिक्स तमाम इंडस्ट्रीज के बारे में कि कहां-कहां बीमार हैं, किस वजह से हैं, उनकी कितनी कैपिटल एरोड हुई है उसकी मशीनरी की क्या स्थिति है, यह मानिटरिंग करना हमारे लिए सम्भव न होगा न तो इस प्रकार की मशीनरी कोई निर्माण कर सकता है ।

श्री सीता राम केसरी : आप जैसे काबिल मंत्री नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है ?

श्री जार्ज फर्नेन्डीस : श्रीमन, 6 लाख छोटे उद्योग हैं इस देश में, बड़े उद्योग कई हजार हैं । अब इन सभी उद्योगों में मशीनरी की क्या स्थिति है, उनकी कैपिटल की क्या स्थिति है, इसका क्लोज मानिटरिंग किसी भी व्यवस्था में सम्भव नहीं हो सकता है । उद्योग क्यों बीमार पड़ गया है, उसके भी कई कारण होते हैं । उसमें यह भी तय करके कहना मुश्किल है कि उसकी मशीनरी खराब होने से ही बीमार हो गई या और कारण भी हैं जैसे बड़े उद्योग वाले छोटे उद्योगों को पैसा नहीं देते, उनके पास पैसा कम है, कहीं मिस मैनजमेंट हो जाता है । ये कई कारण होते हैं । इन सब कारणों को लेकर हमने 15 मई को नीति सदन के सामने रखी है । अगर चाहे सदन तो हम उस नीति पर बहस करने के लिए तैयार हैं और सदस्यों की राय लेकर जो सही रास्ता है उस पर अमल करने के लिए तैयार हैं ।

श्री श्याम लाल यादव : मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जरूर चाहूंगा और मैं समझता हूं, सारा सदन चाहता है कि उस नीति पर जो इन्होंने सदन में रखी है, चर्चा अवश्य की जाए, इसके लिये सरकार समय जरूर दे। लेकिन यह चर्चा जब हो इसके पहले मंत्री जी से एक मौलिक बात मैं जानना चाहता हूं कि सरकार में कोई ऐसा इंडस्ट्रीयल विभाग या दूसरा कोई विभाग अगर इस जिम्मेदारी को उठाने को तैयार नहीं है आज की विषम स्थिति में जो इस देश में औद्योगिक क्षेत्र में उत्पन्न हो गई है क्या वह यह सोच रहे हैं कि उसको मोनिटरिंग के जरिये कि कौन सिक्स है, उनके क्या कारण है, इन सब चीज का अध्ययन किया जाए और इनका निराकरण करने का प्रयास किया जाए ? अगर मंत्री जी यह नहीं करेंगे तो कैसे हम यह विश्वास करें कि मंत्री जी ने जो रुग्णता को दूर करने की बात कही है उसको सही ढंग से क्रियान्वित कर सकेंगे ? सभापति जी, एक बात और जानना चाहता हूं कि इन उद्योगों के बन्द होने में क्या राज्य सरकारों का भी बहुत बड़ा हाथ है ? वे समय से कोई कदम नहीं उठाती हैं और उन उद्योगों के विकास के लिये भी कोई काम नहीं करती है ? मैं अंतिम बात मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि एक जगह मानिटरिंग करने का प्रयास नहीं करेंगे तो जैसा जवाब मंत्री जी दे रहे हैं वैसा ही हर बार जवाब देते रहेंगे अब भी चर्चा इस पर होगी।

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : सभापति जी, मानिटरिंग करने की हमने व्यवस्था की है—बैंकों के जरिये और अपने मंत्रालय के जरिये। हमने बैंकों से कहा है कि वे अपने स्तर पर इस बात की जानकारी हमेशा रखें कि पैसा ठीक ढंग से वापिस आ रहा है या नहीं। अगर बैंकों का पैसा लौट कर नहीं आता है तो मामला बिगड़ जाता है। यह मिसमैनेजमैंट की वजह से या बड़ी न छोटों को नहीं दिया या दूसरे भी कारणों से यह हो सकता है। हम सबसे पहले बैंकों से पता लगा सकते हैं। बैंकों के जरिये रिजर्व बैंक से और रिजर्व बैंक के जरिये इंडस्ट्री मिनिस्टरी से मानिटरिंग की व्यवस्था हम करते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज 6 लाख छोटे कारखाने हैं और हजारों बड़े कारखाने हैं। इन सब के लिये एक मानिटरिंग सिस्टम बना कर यह पता करना कि कौन कब बीमार पड़ेगा यह हमारे लिये संभव नहीं हो सकता।

श्री श्याम लाल यादव : बहस के लिये आपकी क्या राय है ?

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : जब सदन बहस करने के लिये तैयार हो हमें मंजूर है।

श्री टी० अंजैया सभापति जी, इंडस्ट्री मिनिस्टर महोदय ने जैसा कहा कि जो सिक इंडस्ट्रीज हैं उसके कारण शेयर होल्डरों का पैसा खत्म हो जाता है, ये लोग शेयर होल्डर्ज का पैसा खा जाते हैं, बैंकों का पैसा भी खा जाते हैं। मेरा कहना है कि ऐसे लोगों को लाइसेंस मत दीजिए। उनके ऊपर यह पाबन्दी लगा दीजिए कि अगर वह फैक्टरी किसी तरह से मो गारन्टी दे तो वह चल सकेगी अन्यथा नहीं। आप जानते हैं बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसा है जो सिक हैं उनको गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या सैन्ट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को इस बात के लिये कहेगी, चाहे वह प्राइवेट सैक्टर में हो, पब्लिक सैक्टर में हो या को-आपरेटिव सैक्टर में हो, जो सिक इंडस्ट्रीज हैं उनको अपने हाथ में ले ले। जैसा अभी मंत्री महोदय ने बताया कि कई लाख इंडस्ट्रीज हैं जिनके अंदर गड़बड़ी है। इसलिये मैं चहता हूं कि इस बारे में एक इंक्वायरी हो और वह इंक्वायरी हर एक स्टेट से इस बारे में होनी चाहिए और आइंदा जब राज्य सभा मीट करे

उस वक्त इस इंक्वायरी की रिपोर्ट हमारे सामने पेश हो ।

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : सभापति जी, जो जांच करने की बात है वह तो राज्य सरकारों के जरिये करनी पड़ती है । इसके पहले सदन में जब इस प्रकार के प्रश्न उठे थे तब सभी राज्य सरकारों से पूछा गया था कि आपके प्रदेश में बीमार उद्योगों की क्या स्थिति है इसकी हम जानकारी दें । इस बारे में अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग भूमिका रही है । कई राज्यों ने यह लिख कर भेजा है कि हमारे यहां कोई बीमार इंडस्ट्री नहीं है और कई राज्यों ने यह लिख कर भेजा कि जो स्थिति है उसको हम लोग अपने ढंग से हल कर रहे है इसलिये इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है । यह जो आपने सुझाव दिया है कि हम लोगों की तरफ से यह प्रयास किया जाए कि लोगों को पैसा, शेयर होल्डरों का पैसा बैंकों का पैसा गैर इस्तेमाल न हो इसके लिये मैं बताना चाहता हूं कि साधारण आदमी जो अपना पैसा लगाता है उद्योगों में उसको इंडस्ट्री के सिक हो जाने के कारण चोट न लगे इसके लिये जो प्रयास हमें करने चाहिये वह हम कर रहे हैं।

SHRI N. G. RANGA: Sir, as you know, so far as sugar factories and rice mills are concerned, the sucrose content of cane and also rice content of paddy is dependent upon the efficiency of the sugar factories on the one hand and rice mills on the other. The prices that the peasants are able to get, either as cane-producers or paddy-producers, depend so largely upon the efficiency of these sugar mills as well as rice mills. Would the Government be good enough to enquire from the States which are the mills which are not able to extract the requisite minimum percentage of sugar from the sugar-cane on the one side and rice from the paddy on the other and see that those mills which are not good enough to produce those requisite quantities of final products are taken over by the Government? It is very well known that several—may be more than hundred—sugar mills in UP and Bihar are 50 to 60 years old with dilapidated useless and inefficient machinery. The same is the case with the rice mills in Andhra Pradesh, Orissa, West Bengal and several other States. Would the Government take these factors into consideration and get this question examined carefully and ensure that as many of them as are not good enough to be kept there as they are now are taken over by the Government and efficient machinery is introduced therein?

SHRI GEORGE FERNANDES: Sir, my colleague, the Agriculture Minister, is concerned with this question. I shall most certainly convey the views of the Member to him.

SHRI N. G. RANGA: Sir, what is the answer he has given?

MR. CHAIRMAN: He says that he will inform the Agriculture Minister to look into that matter.

प्रो० रामलाल परीख : सभापति जी, जहां तक सिक मिलों का सवाल है, अहमदाबाद में एक लक्ष्मी काटन मिल पिछले एक साल से बन्द है । उसको अभी तक चालू नहीं किया जा सका है । राज्य सरकार ने भी इस संबंध में लिखा है, परन्तु क्या यह सच है कि यहां से भी उसको चालू करने का अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ है और उस मिल को चालू करने की कोशिश भी नहीं हो रही है । मुझे यह भी मालूम हुआ है कि इस संबंध में बैंक का एटीट्यूट भी इतना असहयोगी है कि आगे का कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है । इस वक्त लक्ष्मी काटन मिल में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, लेकिन फिर भी यह मिल चालू नहीं की जा रही है । आपने जो आंकड़े बताये हैं उनमें यह लिखा है कि गुजरात में इस समय 4 सिक फैक्ट्रीज हैं जिनमें 200 वर्कर्स इफेक्टेड हैं और दूसरी 6 फैक्ट्रीज में 251 वर्कर्स इफेक्टेड हैं । लेकिन

जहां तक मुझे जानकारी है, क्या यह सही है कि केवल लक्ष्मी काटन मिल में ही 800 से भी ज्यादा बेरोजगार हैं। ऐसी स्थिति में मैं जानना चाहता हू कि क्या मंत्री महोदय लक्ष्मी काटन मिल को चालू करने के लिए कोई कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : सभापति जी, केवल लक्ष्मी काटन मिल ही नहीं, बल्कि देश में इस समय 30 टेक्सटाइल मिलें बन्द हैं। इन तमाम टेक्सटाइल मिलों के बारे में हम क्या करें, इस बारे में मंत्रालय में इस समय विचार-विमर्श हो रहा है और एक महीने के भीतर इन 30 टैक्सटाइल मिलों के संबंध में कोई निश्चित निर्णय कर लिया जाएगा। इसमें अहमदाबाद की मिलें, बम्बई की मिलें, कानपुर की मिलें और अन्य सभी जगहों की मिलें शामिल हैं।

SHRI KALYAN ROY; I do not know why the Minister today is so evasive. Is he not aware that in 1970-71, a survey was carried out by the Government of West Bengal under Mr. Dhawan, the then Governor, to find out the causes of sickness and it was found out that 45 per cent of the mills became sick because of misappropriation of funds, because of siphoning of funds to other profitable industries, because of mismanagement and fights among the shareholders and directors and other causes arising out of failure on the part of the management? My question is very specific. I would like to know which are the mills which have become sick because of these specific factors. The mills become stick; the workers are starved or thrown out of jobs, but not a single industrialist has become sick so far. After making one industry sick, they meet Mr Fernandes and get more licences. So I would like to know what are the mills which have become sick because of mismanagement. The biscuit factories like the Lily factory in West Bengal are going to be closed. What polity has he got? Is he trying to discipline the industrialists, or is he going to lecture to the workers so that they should not ask for their justified demands?

SHRI GEORGE FERNANDES: Sir, I have not read the report which the West Bengal Government had prepared. I shall certainly find out the report and go through it.

I have not said that sickness is for reasons where employers are not responsible, or where the management is not responsible. On the contrary, I have maintained that, by and large, sickness is because of a number of factors in which perhaps the most important factor is mismanagement. I have said that has been the sheet-anchor in this entire policy declaration and because of this there has been mismanagement. In fact when one mill of the Swadeshi group was declared as sick we went and took over the entire lot of mills. I think there were six or seven mills that we took over at that point of time. And we made it very clear even when the mill was taken over and subsequently in the course of the policy declaration that We shall not tolerate any management, any employer rendering a unit sick and mulcting his unit. But the point that I make is that it is not only mismanagement, there are a number of other factors. The market collapses. For instance, we export ready-made clothes. Suddenly there is free zone export and there is a ceiling put. The export units are not able to export their goods outside the country. There is no domestic market. These units close down. It is unable to pay money to the bank. It is unable to meet the creditors. The unit closes down and there is sickness.

SHRI KALYAN ROY: Which are these units?

SHRI GEORGE FERNANDES: You have a number of such situations. Therefore, if the hon'ble Member refers to any particular case I- am prepared to go into that particular case. Where a unit falls sick before

take-over we invariably go through and inquire into it under the I.D.R. Act. Therefore, if the hon'ble Member suggests that we are not concerned with these issues and that we are only lecturing to the workers that is not correct.

SHRI L. R. NAIK; Mr. Chairman, Sir, I am confident that the hon'ble Minister is aware that many small-scale industries are becoming sick day by day as a result of, perhaps, lack of facilities for marketing their products or for lack of salesmanship or other managerial facilities. May I know, therefore, from the hon'ble Minister whether the Government is contemplating to create any central organisation to take up this marketing or to educate the entrepreneurs on marketing techniques or in some cases to take over the products and market themselves?

SHRI GEORGE FERNANDES: Through the District Industrial Centre we are setting up a marketing mechanism. We are training marketing managers for our District Industrial Centres. We hope that at the district level, later at the State level and then at the Central level we shall have adequate marketing facilities and expertise to help the small-scale industries in the country.

श्री प्रेम मनोहर : सभापति महोदय, जो बड़ी इंडस्ट्रीज सिक होती हैं उसमें पहले इंडस्ट्रीज सिक नहीं होती है, पहले मेनेजमेंट सिक होता है। जैसे कि अभी आपने बताया कि कानपुर में स्वदेशी काटन मिल और बाम्बे में नेशनल रेयंस सिक हुआ। जो भी सिक होती है उसमें दो तीन साल बराबर समय लगता है। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की बात छोड़ दीजिए लेकिन जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, आर्गेनाइज्ड सेक्टर में होती है, उनमें पहले मेनेजमेंट सिक होता है जिसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके पास सारी सुविधाएं हैं। तो छोटी इंडस्ट्रीज को छोड़ कर जो बड़े-बड़े उद्योग हैं उन उद्योगों को आपका मंत्रालय तीन साल तक बैठा देखता रहता है। क्यों देखता रहता है? जब वे इंडस्ट्रीज सिक हो जाएंगी तब उस पर विचार करेंगे। पहले साल में डिविडेंड कम होता है, फिर प्रोफिट कम होता है और इस तरह से हालत बराबर गिरती जाती है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि दो तीन साल तक आपका मंत्रालय क्यों नहीं विचार करता कि यह इंडस्ट्री सिक होने वाली है और उसको सिक होने से बचाया जाए?

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : सभापति महोदय, मैंने पहले कहा कि जो सिक इंडस्ट्रीज के बारे में नीति बनाई है उससे पहले कोई भी मोनीटरिंग की व्यवस्था नहीं थी लेकिन अब इस नीति के चलते यह व्यवस्था की गई है कि इलनेस को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। यह तय करने के लिए मोनीटरिंग की व्यवस्था की गई है . . .

श्री कल्याण राय : राष्ट्रीयकरण कर दीजिए . . .

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : आपके पास तो हर एक बीमारी का एक ही इलाज है।

MR. CHAIRMAN: Hon'ble Minister need not reply this.

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : तो इसके लिए मोनीटरिंग सेल बनाया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को यह कहा है कि उनके डाइरेक्टर्स अब सारी इंडस्ट्रीज में चले जाएंगे और जहां इस प्रकार की सिकनेस की कोई भी गुंजाइश नजर आती है वह हमको सारी ऐसी सूचना देने का काम करेंगे जिसके आधार पर यह प्रयास करेंगे कि इंडस्ट्री बीमार न होने पाए।

श्री कल्प नाथ राय : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में पांच हजार स्माल स्केल यूनिट बीमार हैं और 45 शूगर मिल्स सिक डिक्लेयर की गई हैं। उत्तर प्रदेश में आपने

जयपुरिया ग्रुप को गवर्नमेंट के अधीन लिया है, इस बात की बड़ी चर्चा है कि जयपुरिया मिल को लेकर आपने बड़ा अच्छा काम किया है। मै यह जानना चाहता हूं कि क्या आपकी सरकार विचार कर रही है कि पुनः जयपुरिया ग्रुप के हाथों में इसे वापिस दे दिया जाए ?

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : सभापति जी, सरकार की बिलकुल साफ नीति है कि जहां कोई भी मिस-मैनेजमेंट के चलते या किसी अन्य कारण से आई० (डी एण्ड आर) एक्ट के अन्दर एक बार हम कोई भी यूनिट ले लें अपने हाथ में तो फिर उसको उसके मालिक को देने का सवाल नहीं उठता है और इसलिए जयपुरिया को उनका उद्योग देने का सवाल नहीं उठता है ।

PROF. SOURENDRA BHATTA-CHARJEE: I would like to know if any proposal of the West Bengal Government for the takeover of sick industries is pending with the Industry Ministry and, if so, their number?

SHRI GEORGE FERNANDES: Sir, I shall need notice for that question. But I would like to mention about Lily Biscuits, about which another hon. Member also spoke. We have this Lily Biscuits case in our hands. We have been discussing it with the State Government and also with a number of other interested parties as to how best to settle this problem.

SHRIMATI AMBIKA SONI: Sir, I am glad to hear that the hon. Minister acknowledges the fact that mismanagement also is one of the reasons for declaring the mills as sick and he will look into it so that it does not become like a racket so that some industries are declared as bad and not profitable but carry on their activity. This assurance was given to us even a year and half before and we have been patient for a half year more. But I would like to know from the hon. Minister if it has come to his notice—when he says that the textile trade involved in the export of garments is very profitable for our people—that these people had suffered and many had to close down their factories because of the restrictions imposed by various foreign Governments. But has it come to the notice of the hon. Minister that it is also decided by the Government to auction the licences for export so that the very big business houses which are dealing in the export of garments are able to purchase all the licences for export—the quota which was there for export—and they throttle the smaller people, the smaller units in this particular trade and thereby forcing these people to close down their units? Is it his attempt to give more equitable social justice or whatever he speaks about? I want to know whether he is doing anything so that the smaller units are not made to close down because the Government has decided to sponsor the bigger units and give them all the export of garments?

SHRI GEORGE FERNANDES: Sir, the hon. Member has addressed the question to the wrong Minister. This question should be addressed to the Commerce Minister. But, in any case, I am not aware of any such thing.

SHRI KHURSHED ALAM KHAN: Sir, the hon. Minister, while identifying the reasons for industries falling sick, has said that it is general mismanagement, but it is too general a term. I would like to know specifically whether absence of professional management is one reason and improper accountability is another reason. Besides, a specific example is given now. I would like to ask him whether he is aware of the Kohinoor Mills of Bombay and the soft loan provided to them and what they have done about it. What action has his Ministry taken in this matter?

SHRI GEORGE FERNANDES: Sir, I would need notice to answer the point about Kohinoor Mills. Where sickness is concerned, I have already explained the reasons.

SHRI MANUBHAI PATEL: I Rm glad that the Government has taken

steps in the right direction in taking over certain sick industries which were running in loss or which were not running at all and I am also glad that after the takeover, from the very next month, they are running in profit. May I know what is the policy of the Government with regard to such of those industries where the investment of private people is there and also where the industries have to pay to the customers? What will be the policy of the Government where such dues are there? Will they take over them also?

SHRI GEORGE FERNANDES: Sir, when we take over a unit, there are certain priorities that are laid down. The first priority, in the last 16 months at least, has been to meet the dues of the workers. Thereafter such financial institutions and Government outstandings that are there are given the next chance. Thereafter, if the monies are still available, if the company's overall assets still enable us to meet other liabilities, the other liabilities are met.

SHRI GIAN CHAND TOTU: May I know from the hon. Minister what steps his Ministry is proposing to take in cases where sickness does not develop because of mismanagement but because of such other factors as shortage of power higher rates of interest, lack of market, etc.? What are the steps that his Ministry is going to take to rehabilitate such industries?

SHRI GEORGE FERNANDES: Sir, all the work that we do is meant for that purpose.

Memorandum from the Employees' Union of the National Project Construction Company

t*622. SHRI BHOLA PRASAD: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government have received any memorandum dated the 10th July, 1978 from the Employees' Union of National Project Construction Company, Hundru, Ranchi, Bihar;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what steps Government have taken in the matter?

THE MnN29TER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a) to (c) The Government has not received any memorandum dated the 10th July, 1978 from the Employees' Union of National Projects Construction Corporation, Hundru, Ranchi, Bihar. However, the above mentioned Union had made certain demands on 2nd May, 1978, which have been processed as per the standing procedures under the auspices of the Labour Department of the Government of Bihar.

This matter is being dealt with by the State Government, who, after consideration of the various aspects involved and after discussions with the Union's representatives and the local N.P.C.C. officials, have referred the matter for adjudication by the Labour Court, Ranchi. The State Government have also prohibited the continuance of any strike in connection with the dispute.

श्री भोला प्रसाद : सभापति महोदय, यह कम्पनी सैन्ट्रल गवर्नमेंट के मातहत काम करती है और अगर यह मामला श्रम अदालत में दिया गया है तो फिर यूनियन और मैनेजमेंट के बीच इस मामले को वापिस किया जा सकता है और मामले को सुलझाया जा सकता है। इस के लिये वाजिब कदम उठाने के रास्ते में कानून बाधक नहीं है।

सभापति महोदय, यह कम्पनी एक अस्थाई कम्पनी है और यह अस्थायी उद्योग है और इसके जो सर्टिफाइड स्टेंडिंग आर्डर हैं इसके मुताबिक इसके अन्दर काम करने

tPreviously Starred Question 572 transferred from the 11th August, 1978.